

The Uttar Pradesh Jal-Sambharan Tatha Sewer Vyavasth (Sanshodhan) Adhiniyam, 1978

Act 28 of 1978

Keyword(s):

Drain, Drainage, Executive Engineer, Licenced Plumber, Occupier, Service Pipe, Sewage, Sewer, Street, Supply Pipe, Trade Effluent, Trade Refuse, Trunk Main, Water Course, Water Fittings

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

160350

L. A. 15/78:284 Cerp. 2-

विधान प्राचित्र स्थाप्त । (राजकोय स्थाप्त)

उत्तर प्रदेश जल-संभरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) ग्रिधिनियम, 1978 [उत्तर प्रदेश ग्रिबिनियम तंक्का 28, 1978]

('भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 16 सितम्बर, 1978 ई 0 ो अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग 1—खण्ड (क) दिनांक 18 सितम्बर, 1978 ई 0 को प्रकाशित हुआ।)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 31 श्रगस्त, 1978ई 0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् दिनांक 9 सितम्बर, 1978ई 0 की बैठक में स्वीकृत किया ।]

उत्तर प्रदेश जल-संभरण तथा सीवर व्यवस्था ग्रधिनियम, 1975 का संशोधन करने केलिए ग्रधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित ग्रधिनियम बनाया जाता है:—

1—(1) यह ग्रधिनियम उत्तर प्रदेश जल-संभरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) ग्रधिनियम, 978 कहा जायगा ।

(2) यह 1 ग्रगस्त, 1978 को प्रवृत्त समझा जायगा।

Price 25 Paise

संक्षिप्त नाम झौर प्रारम्म

[उद्देश्य ग्रौर कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 24 ग्रगस्त, 1978 ई 0 का सरकारी साधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग 3-खण्ड (क) देखिये।] जत्तर प्रदेश ग्रिधिनियम संस्या 43, सन् 1975 की घारा 1 का संशोधन

द्यारा ्र 4 का संशोधन 2--उत्तर प्रदेश जल-सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था ग्रधिनियम, 1975 की, जिसे ग्रागे मूल श्रिधिनियम कहा गया है, धारा 1 में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, ग्रर्थात्--

"(3) इसे 18 जून, 1975 से प्रवृत्त समझा जायगा ।"

3--मूल् प्रधिनियम की धारा 4 में--

(एक) उपधार्रा (2) में, खंड (छ) में, शब्द "तीन" के स्थान पर शब्द "पांच" रख दिया जायगा ;

(दो) उपधारा (4) के स्थान पर्दं निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, ग्रर्थात्--

"(4) निगम की बैठक में स्वयं उपस्थित होने के बजाय बैठक में उपस्थित होने के लिए, उपधारा (2) के खंड (ग) या खंड (घ) में निर्दिष्ट सदस्य अपने विभाग में उप सचिव से अनिम्न पद के किसी अधिकारी को, उक्त उपधारा के खंड (ङ) में निर्दिष्ट सदस्य अपने विभाग में उप निदेशक से अनिम्न पद के किसी अधिकारी को और उक्त उपधारा के खंड (च) में निर्दिष्ट सदस्य अपने विभाग में संयुक्त निदेशक से अनिम्न पद के किसी अधिकारी को, प्रतिनियुक्त कर सकता है। इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी को बैठक की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा और मत देने का भी अधिकारी होगा।"

धारा 18 **का** संशोधन 4--मूल ग्रिधिनियम की धारा 18 में, उपधारा (3) में, शब्द "जल संस्थान" के पश्चात् के शब्द "जो धारा 20 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट जल संस्थान न हो," रख दिये जायेंगे।

धारा 19 के स्थान पर नयी धारा का रखा जाना 5--मूल मधिनियम की धारा 19 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, मर्थात्--

"19-राज्य सरकार ग्रधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकती है कि ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में, जो ग्रधिसूचना में विनिर्दिष्ट हों ग्रौर जिनके जल संस्थान के रूप लिए धारा 18 के ग्रधीन कोई जल संस्थान स्थापित न किया में जल निगम गया हो, इस ग्रधिनियम के उपबन्धों के ग्रधीन जल संस्थान की सभी या किन्हीं शक्तियों, कर्त्तव्यों ग्रौर कृत्यों का प्रयोग, पालन

या सम्पादन जल निगम द्वारा किया जायेगा श्रीर तदुपरान्त ऐसी शक्तियों, कर्त्तव्यों या कृत्यों का प्रयोग, पालन या सम्पादन करने के प्रयोजनार्थं जल निगम को जल संस्थान समझा जायगा श्रीर ऐसी अधिसूचना के दिनांक को जल संस्थान के गठन का दिनांक समझ। जायेगा।"

धारा 20 के स्थान पर नयी धारा का रखा जाना

6—मूल ग्रधिनियम की धारा 20 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, ग्रथीत्— "20—(1)नगर महापालिका के स्थानीय क्षेत्र पर ग्रधिकारिता के लिए गठित जल-संस्थान में एक ग्रध्यक्ष, जो नगर महापालिका का नगर प्रमुख जल संस्थान का गठन (पदेन) होगा, ग्रौर निम्नलिखित ग्रन्य सदस्य होंगे, ग्रथीत्:—

(क) एक महाप्रबन्धक, जिसे राज्य सरकार के अनुमोदन से निगम द्वारा नियुक्त किया जायगा, जो प्रशासकीय अनुभव और जल-संभरण और सीवर व्यवस्था संबंधी कार्यों का भी अनुभव रखने वाला अहित अभियंता होगा;

(ख) स्वास्थ्य सेवा का एक संयुक्त निदेशक, जिसे स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायगा;

(ग) नगर महापालिका के तीन सभासद, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायगा;

(घ) निगम के दो प्रतिनिधि;

(ङ) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश;

(च) नगर महापालिका के मुख्यक्रनगर ग्रधिकारी ।

(2) म्युनिसिपल बोर्ड के स्थानीय क्षेत्र पर ग्रधिकारिता का प्रयोग करने के लिए गठित जल संस्थान में एक ग्रध्यक्ष जो म्युनिसिपल बोर्ड का प्रेसीडेंट (पदेन) होगा, ग्रौर निम्नलिखित ग्रन्य सदस्य होंगे, ग्रर्थात् :—

(क) एक महाप्रबन्धक, जिसे राज्य सरकार के अनुमोदन से निगम द्वारा नियुक्त किया जायगा, जो प्रशासकीय अनुभव और जल-सम्भरण और सीवर व्यवस्था संबंधी कार्यों का भी अनुभव रखने वाला अहित अभियंता होगा;

(ख) जिला मजिस्ट्रेट के ग्रधीनस्थ कोई ग्रधिकारी, जिसे जिला-मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा;

(ग) निगम के दो प्रतिनिधिः

(घ) उस जिले का, जहां जिले का प्रधान कार्यालय स्थित हो, उप मु**ख्य** चिकित्सा ग्रधिकारी (स्वास्थ्य);

(ङ) एक ग्रधिकारी, जिसे स्थानीय निकाय निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा नाम-निर्दिष्ट

किया जायगा; 🐧

(च) म्युनिसिपल बोर्ड के दो निर्वाचित सदस्य. जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा।

- (3) किसी ग्रन्य जल-संस्थान में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक ग्रध्यक्ष होगा ग्रौर निम्नलिखित भ्रन्य सदस्य होंगे, भ्रर्थात्-
 - (क) उस जिले का, जहां जल-संस्थान का प्रधान कार्यालय स्थित हो, कलेक्टर, पदे
 - (ख) सामुदायिक विकास विभाग का ज्येष्ठतम ग्रधिकारी जिसका मुख्यालय जल संस्थान के क्षेत्रान्तर्गत हो;
 - (ग) एक महाप्रबन्धक, जिसे राज्य सरकार के अनुमोदन से निगम द्वारा नियुक्त किया जायगा जो प्रशासकीय अनुभव और जल-संभरण और सीवर व्यवस्था संबंधी कार्यों का भी म्रनुभव रखने वाला म्रहित म्रभियंता होगा;
 - (घ) निगम के दो प्रतिबिध;
 - (ङ) जल संस्थान की अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक जिले के स्थक्नीय निकायों के निर्वाचित ग्रध्यक्षों या सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक व्यक्ति:

प्रतिबन्ध यह है कि जहां जल-संस्थान की ग्रधिकारिता के ग्रन्तर्गत ग्राने वाले जिलों की संख्या पांच से कम है वहां ऐसे नाम-निर्दिष्ट व्यक्तियों की संख्या पांच होगी बिजनमें से प्रत्येक जिले से कम से कम एक व्यक्ति होगा;

(च) उस जिले का, जहां जल-संस्थान का मृध्यालय स्थित हो, मुख्य चिकित्सा ग्रधिकारी ।''

7—मूल श्रधिनियम की धारा 25 में, उपधारा $(2)^{\text{F}}$ में, खंड (6) में, निम्नलिखित प्रति-बन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जायगा, श्रर्थात् :---

वारा 25 का संशोधन

"प्रतिबन्ध यह है किंँटैरिफ लगाने या उसमें संशोधन करने का विनिश्चय नहीं किया जायगा जब तक कि ऐसी नोटिस, जो विहित की जाय, देने के पश्चात् लाये गये विशेष प्रस्ताद को जल-संस्थान की कुल सदस्य संख्या के दो तिहाई के यहुमते से पारित न कर दिया गया हो।"

8--मूल श्रधिनियम की धारा 49 में,--

49 কা घारा संशोध न

(एक) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जासगी, अर्थात्:---

"(2-क) यदि किसी समय राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि किसी जल-संस्थान या स्थानीय निकाय ने, यथास्थिति, जल-सम्भरण या सीवर व्यवस्था संबंधी सेवाभ्रों या दोनों का कुप्रबन्ध किया है, या उसकी सम्पत्ति को हानि पहुंचायी है तो वह, जल-संस्थान या स्थानीय निकाय को स्पष्टीकरण का अवसर देने के पश्चात् भ्रादेश द्वारा उस जल-संस्थान या स्थानीय निकाय की जल-संभरण या सीवर-व्यवस्था संबंधी सेवाग्रों का अन्तरण सीधे निगम को कर सकती है, श्रौर ऐसा आदेश तीन वर्ष से म्रनिधक ऐसी म्रविध के लिए प्रभावी होगा जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय:

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार ग्रपने मूल आदेश के कार्यान्वयन की अवाध को समय-समय पर ब्रादेश द्वारा इस प्रकार वड़ा सकती है कि ऐसी वृद्धि की कुल ग्रवधि दो वर्ष से ग्रधिक न हो।"

(दो) उपधारा (3) में, शब्द, कोष्ठक ग्रीर ग्रंक "उपधारा (1) के उपबन्धों" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक, ग्रंक ग्रीर ग्रक्षर "उपधारा (2) या उपधारा (2-क) के इपबन्धों" रख दिये जायेंगे।

(तीन) उपधारा (4) में, शब्द, कोव्ठक ग्रौर ग्रंक "उपधारा (2) के ग्रधीन" के स्थान पर शब्द, कोव्ठक, ग्रंक ग्रौर ग्रक्षर "उपधारा (2) या उपधारा (2-क) के ग्रधीन" रख दिय जायेंगे।

धारा 99 का संशोधन 9-मूल ग्रिधिंनियम की घारा 99 में-

(क) उपधारा (2) में शब्द और ग्रंक "15 ग्रागस्त, 1976" के स्थान पर शब्द ग्रीर ग्रंक "30 सितम्बर, 1978" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (3) निकाल दी जायगी।

संक्रमणकालीन उपबन्ध 10—जहां जल संस्थान की शक्तियां मूल अधिनियम की धारा 19 के, जैसी कि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व थीं अधीन नगर महापालिका को प्रवत्त कर वी गयी हों, वहां महापालिका इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम में किये गये किसी संशोधन के होते हुए भी, ऐसी शक्तियों का तब तक प्रयोग करती रहेगी जब तक कि इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन ऐसी नगर महापालिका के स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता वाले जल संस्थान का गठन न कर विया जाय।

निरसन ग्रौर ग्र**प**वाद 11--(1) उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) ग्रध्यादेश, 1978 एतवृद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त श्रध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल श्रधिनियम के श्रधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस श्रधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल श्रधिनियम के तत्समान उपबन्धों के श्रधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस श्रधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

उत्तर प्रदेश ग्रध्यादेश संख्या 17, सन् 1978